नौ शहरों में नई टाउनशिप के लिए ₹1,285 करोड़

प्राधिकरणों व आविप को 14 योजनाओं के लिए दी गई धनराशि

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ: राज्य के नौ शहरों में 14 नई टाउनशिप विकसित करने के लिए विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद (आविप) को 1,285 करोड़ रुपये दिए गए हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के तहत आठ विकास प्राधिकरणों व आविप को भूमि अर्जन के लिए बतौर सीड कैपिटल धनराशि दी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 22 नवंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। मंगलवार को जारी संबंधित शासनादेश के अनुसार 1285 करोड़ रुपये में से सर्वाधिक 400 करोड़ रुपये आविप को लखनऊ व अयोध्या की तीन योजनाओं के लिए दिए गए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण को दो योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपये मिले हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण को 200 करोड़, दो योजनाओं के लिए मथुरा-वृंदावन को 175 करोड़, सहारनपुर को 75 करोड़, मुरादाबाद को 50 करोड़, फिरोजाबाद को 40 करोड़, खुर्जा को 25 करोड़ व बांदा विकास प्राधिकरण को 20 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

नौ योजनाओं के भूमि अर्जन पर 4164.16 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है लेकिन पहली किस्त के तौर पर 1,285 करोड़ रुपये दिए गए हैं। दी गई धनराशि के बराबर संबंधित प्राधिकरण व परिषद को अपने पास से मैचिंग राशि भी मिलानी होगी। 75 प्रतिशत धनराशि खर्च होने का प्रमाणपत्र देने के बाद ही दूसरी किस्त जारी की जाएगी। प्राधिकरण-आविप को प्रस्तावित टाउनशिप में पर्याप्त पेयजल व भू-गर्भ जल संरक्षण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।

सीएम योगी आदित्यनाथ • फाइल

- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण व नए शहर प्रोत्साहन योजना को लगेंगे पंख
- एलडीए को 300 करोड़, मेरठ को 200, मथुरा को 175 करोड़ रुपये
- आविप को सीड कैपिटल के तौर पर दिए गए 400 करोड़ रुपये

लखनऊ की चार योजनाओं का रास्ता साफ

600 करोड़ शासन ने लखनऊ को दिए

जासं, लखनऊ: आवास विकास परिषद व लखनऊ विकास प्राधिकरण की चार योजनाओं के लिए 600 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल गई है। इन योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण तेज होगा। एलडीए की आइटी सिटी और वेलनेस सिटी योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपये, जबकि आवास विकास परिषद की मोहनलालगंज स्थित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना-एक व तीन के लिए 300 करोड़ जारी किए गए हैं।

एलडीए की आइटी सिटी योजना में बक्कास, सोनई कंजेहरा, सिकंदरपुर, अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, पहाड़नगर, टिकरिया, रकीबाबाद, मोहरीखुद, खुजौली व भटवारा आदि गांवों की भूमि अधिग्रहीत की जानी है, जबकि वेलनेस सिटी के लिए चौरहिया, चौरासी, मलकूपुर, दुलारमऊ, बक्कास, नूरपुर, बेहटा व मस्तेमऊ में भूमि अधिग्रहण होना है। शासन द्वारा सीड कैपिटल के रूप में वेलनेस सिटी के लिए 206.85 करोड़ व आइटी सिटी के लिए 197.85 करोड़ अनुमन्य है। दोनों योजनाओं के लिए 150-150 करोड़ जारी हो गए हैं। आवास विकास परिषद की भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना-1 मोहनलालगंज के लिए 150 करोड़ शामिल हैं। योजना में चांदसराय, कासिमपुर, विरूहा, हबुआपुर, मोअज्जमनगर, सठवारा, सिद्धपुरा, भटवारा, पहाईनगर, टिकरिया, कबीरपुर, मगहुआ व बेली गांव शामिल हैं। मोहनलालगंज तीन के लिए भी 150 करोड़ रुपये मिले हैं। योजना में हबुआपुर, बेली, शिवलर, देहरामऊ, पहासा व सिठौलीकला गांव शामिल हैं।